

UNEP की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024

प्रलिस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र (UN), अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC)

मेंस के लिये:

जलवायु वतितपोषण में सुधार की आवश्यकता, जलवायु अनुकूलन वतितपोषण में चुनौतियाँ

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024: [\[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\] \[?\]](#) (*Adaptation Gap Report 2024: Come hell and high water*) जारी की।

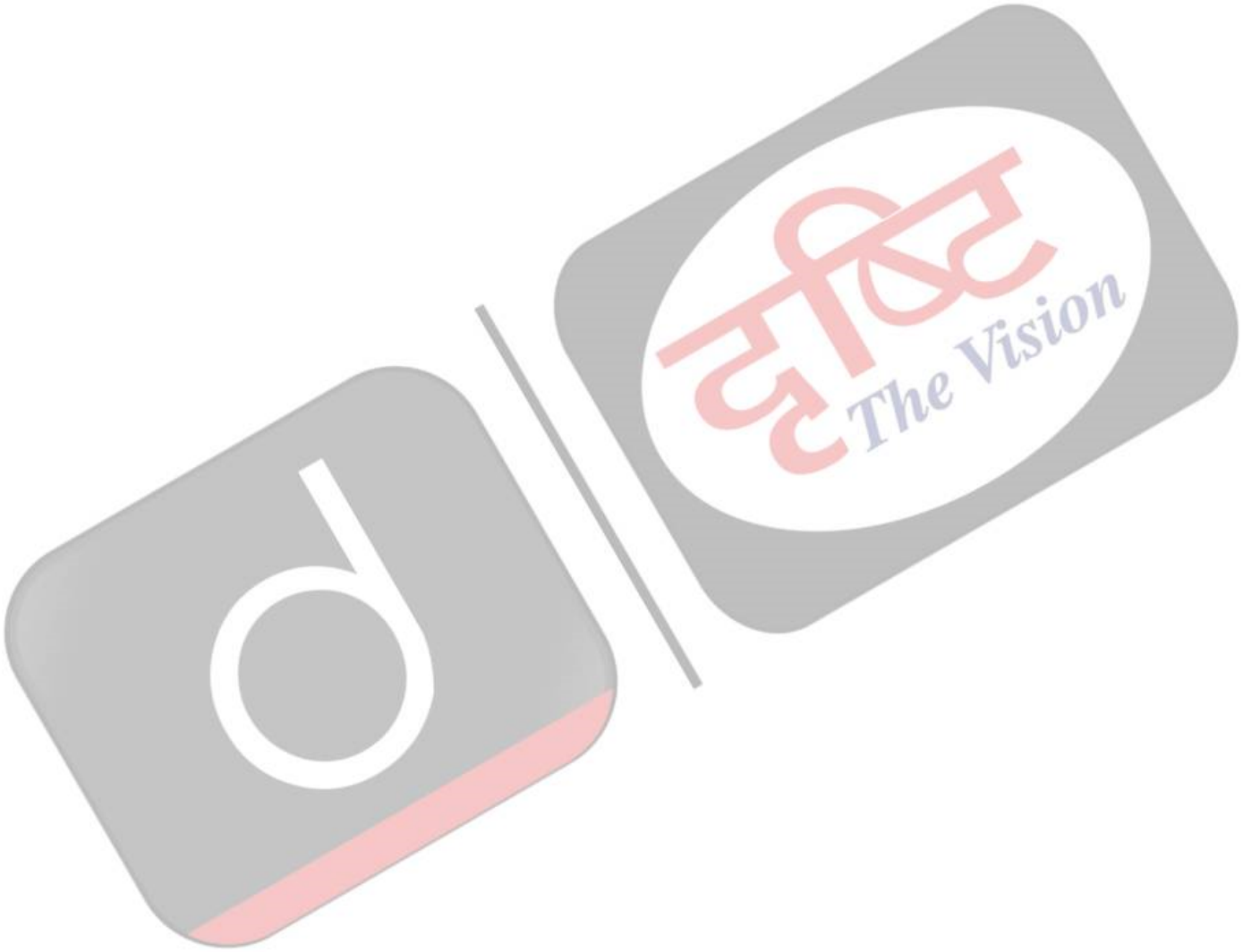
- इस रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन पर्याप्तों में वृद्धि की आवश्यकता पर बल (वशिष रूप से विकासशील देशों के लिये अनुकूलन वतितपोषण के संबंध में) दिया गया है।

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के प्रमुख नषिकरष क्या हैं?

- अडैप्टेशन वतित अंतराल:** अडैप्टेशन वतित अंतराल (जो वतितपोषण आवश्यकताओं एवं वास्तविक नधियों के बीच असमानता को दर्शाता है) बढ़ गया है।
 - वर्तमान वतितपोषण (वर्ष 2022 के अनुसार), आवश्यकताओं से काफी कम है जिसमें केवल 28 बलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं- जो [ग्लासगो जलवायु समझौते](#) के तहत अनुमानित आवश्यकताओं का केवल 5% ही है।
 - ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम से कम 30% तक कम करना है।
 - UNEP का अनुमान है कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिये वर्ष 2030 तक प्रतवर्ष 387 बलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
 - वतितपोषण की कमी: अनुकूलन वतितपोषण अंतराल का केवल एक तह्रिई हसिसा ही ऐसे क्षेत्नों में है, जो आमतौर पर नजि क्षेत्न द्वारा वतितपोषित होते हैं, जिससे नजि नविश के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं।
 - ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव: [उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2024](#) से संकेत मलिता है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.6°C से 3.1°C तक बढ़ सकता है।
 - वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद विकासशील देश जलवायु-प्रेरित मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक पीड़ित हैं।
 - नेपाल, नाइजीरिया और चाड में हाल में आई बाढ़ से इन देशों की वतितयी और ढाँचागत कमजोरियों पर प्रकाश पड़ा है।
 - राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) की प्रगतः 171 देशों की कम से कम एक अनुकूलन नीति है लेकिन बिना अनुकूलन नीति वाले 26 देशों में से 10 देश इसे विकसित करने में रुचि नहीं रखते हैं, जिससे NAP नयोजन एवं कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर प्रकाश पड़ता है।
 - UNFCCC COP28 में प्रस्तुत वैश्विक जलवायु अनुकूलन हेतु UAE फ्रेमवर्क (UAE-FGCR) के तहत अनुकूलन के क्रम में वशिषगत लक्ष्य (जैसे, कृषि, जल, स्वास्थ्य) नरिधारति कथि गए हैं, फरि भी इनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है।
 - यह अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र है जिसका प्राथमिक लक्ष्य जलवायु अनुकूलन है।
 - परिवर्तनकारी अनुकूलन: UNEP द्वारा प्रतकिरयितमक से रणनीतिक अनुकूलन की ओर बदलाव का आह्वान कथि गया है, जिसमें पारसिथितिकी तंत्र संरक्षण एवं सांस्कृतिक वरिसत जैसे क्षेत्नों पर बल दिया गया है।
 - "परिवर्तनकारी अनुकूलन" की अवधारणा COP28 के दौरान वविदास्पद थी लेकिन बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिये इसे महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
 - परिवर्तनकारी अनुकूलन से तात्पर्य उन कार्यों से है जो वर्तमान प्रथाओं में मात्र समायोजन से परे, संरचना या कार्य में

पर्याप्त परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं।

॥





UAE FGCR THEMATIC AREAS

Health

- Risk assessment and monitoring
- Awareness and communications

Infrastructure and settlements

- Risk assessment and management
- Climate smart infrastructure

Cultural heritage

- Climate proofing
- Community engagement

Poverty and livelihoods

- Diversifying livelihoods
- Reskilling in vulnerable sectors

Ecosystems and biodiversity

- Risk assessment and monitoring
- Ecosystem-based approaches
- Community engagement

Food and agriculture

- Climate smart agriculture (techniques and technologies)
- Climate resilient food systems

Water

- Risk assessment and monitoring
- Community engagement
- Regulations

ITERATIVE ADAPTATION POLICY CYCLE

Impact, vulnerability and risk assessment

- Data collection and access
- Risk and vulnerability assessment

Planning

- Capacity assessments
- Cross-sectoral planning and budgeting

Implementation

- Use of adaptation technologies
- Community engagement

Monitoring, evaluation and learning

- Data collection and monitoring
- Institutional learning

ENABLING FACTORS

Data, knowledge and communications

- Communication and knowledge networks
- Data collection and access

Educational and capacity building infrastructure

- Integrating adaptation into education systems
- Training for public officials

Institutional arrangements

- Mainstreaming gender
- Regulations
- Climate literacy in government

Financing

- Proposal preparation
- Climate risk assessment

Engagement

- Gender-responsive outreach and communication
- Networks for dialogue and exchange

Leadership

- Strategic leadership
- Results-based management

Source: Adapted from NAP Global Network (2023) and the UAE FGCR.

विकासशील देशों हेतु जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमिति वित्तीय क्षमता:** समुद्र के किनारे दीवार नरिमाण, अनुकूल बुनयािदी ढाँचा और जल सुरक्षा जैसी अनुकूलन परियोजनाएँ विकासशील देशों के लयि वित्तीय रूप से बोझलि होती हैं ।
- **वकिसति देशों के योगदान में कमी:** जलवायु समझौतों के तहत दायित्वों के बावजूद, वकिसति राष्ट्र वादा कयि गए वित्तीय समर्थन (वशिष रूप से वर्ष 2020 के लयि नरिधारति 100 बलियिन अमेरकी डॉलर के लक्ष्य) को पूरा करने में काफी पीछे हैं ।
- उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर नरिभरता: वर्तमान वित्तपोषण का अधिकांश हसिसा उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर आधारति है, जसिसे ऋण बोझ बढ़ने के साथ प्राप्तकर्त्ता देशों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है ।
- **COP29 में वित्तीय प्रतबिद्धता की तात्कालकितता:** वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का लक्ष्य केवल आंशकि रूप से ही इस अंतराल को कम करने में सक्षम है ।

जलवायु परिवर्तन से नपिटने के लयि कयि गए प्रयास और प्रतबिद्धताएँ क्या हैं?

- **वैश्वकि प्रयास:**
 - ग्लासगो जलवायु समझौता और वित्तपोषण लक्ष्य को दोगुना करना: UNFCCC COP26 में वकिसति देशों ने अनुकूलन वित्त को वर्ष 2019 के 19 बलियिन अमेरकी डॉलर के स्तर से वर्ष 2025 तक दोगुना करते हुए 38 बलियिन अमेरकी डॉलर तथा वर्ष 2030 तक एक नया जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य स्थापति करने की प्रतबिद्धता व्यक्त की है ।
 - **ADB जलवायु अनुकूलन नविश योजना कार्यक्रम (एशियाई वकिस बैंक 2023):** यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है जो ADB से संबंधति विकासशील सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन प्राथमकितताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलन नविश योजनाएँ बनाने में सहायता करता है ।
 - **UNDP अडेप्टेशन एक्सलेरेटर (UNFCCC 2024): UNDP-अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सलेरेटर (AFCIA)** एक ऐसा कार्यक्रम है जसिके तहत समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रतबिद्धता लचीला बनने में मदद करने के क्रम में स्थानीय स्तर पर संचालति अनुकूलन प्रथाओं का समर्थन कयि जाता है ।
- **भारत के प्रयास:**
 - आरथकि सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2021-2022 में भारत का जलवायु लचीलापन एवं अनुकूलन खर्चसकल घरेलू उत्पाद का 5.6% था ।
 - वित्तीय वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण 13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 17% हो गया है ।
 - UNFCCC कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ (COP26) के 26वें सत्र में भारत ने अपनेराष्ट्रीय स्तर पर अभनिरिधारति योगदान (NDC) के रूप में पाँच अमृत तत्त्व (पंचामृत) प्रस्तुत कयि ।

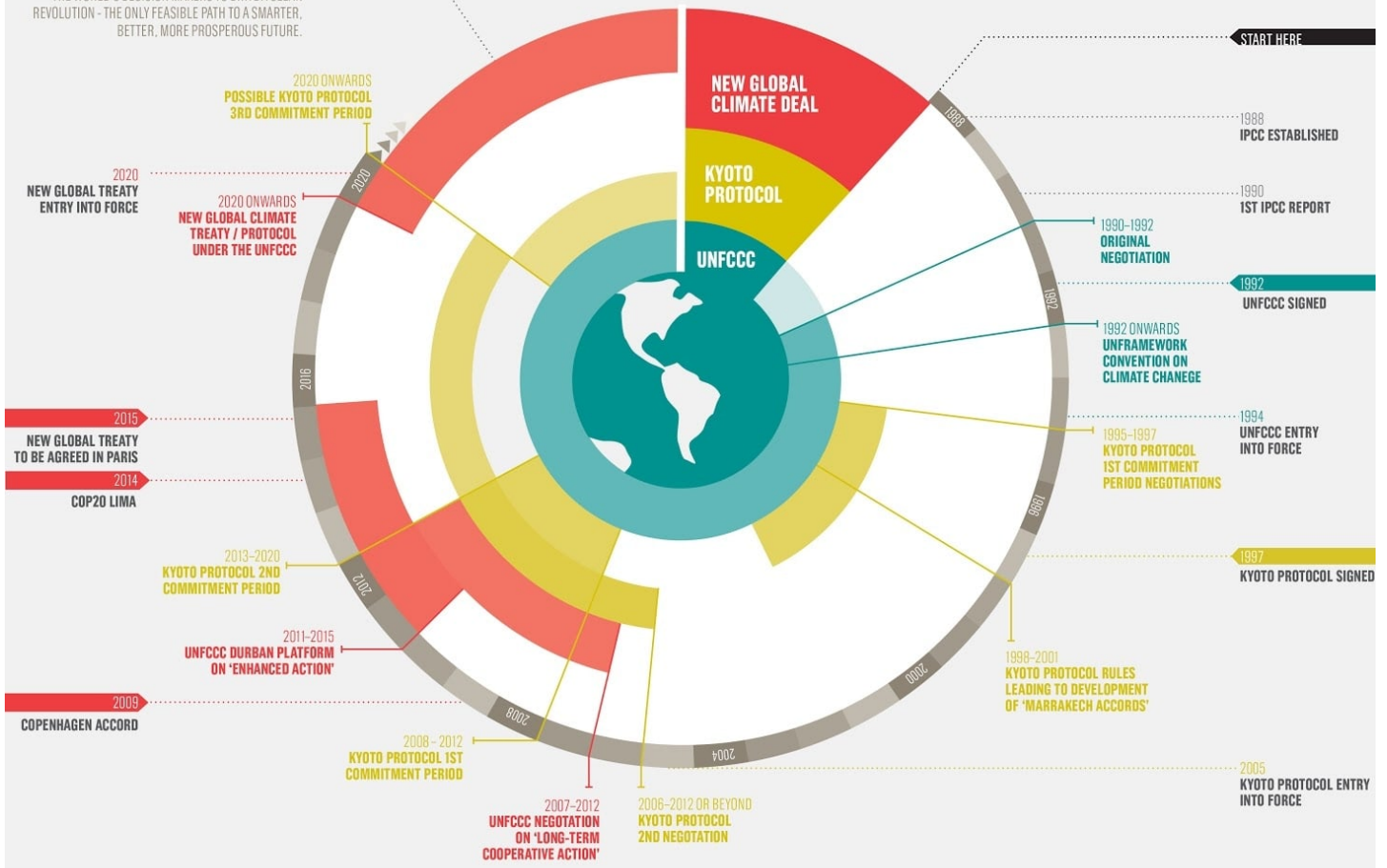
जलवायु वित्तपोषण

- इसका तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है- जो सार्वजनकि, नजी और वैकल्पकि वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त होता है- जसिका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से नपिटने के लयि शमन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना है ।
- UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरसि समझौते के तहत वकिसति देशों से अपेक्षा की गई है कवि वेसमान लेकनि वभिदति उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत का पालन करते हुए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें ।

आगे की राह

- **मज़बूत वित्तीय व्यवस्था:** इस रपिर्स्ट में अनुकूलन प्रयासों को समर्थन देने के लयि मज़बूत वित्तीय प्रतबिद्धता की आवश्यकता पर बल दयिा गया है ।
- **वित्तपोषण मॉडल:** इस रपिर्स्ट में वैकल्पकि वित्तपोषण मॉडल के रूप में जोखमि वित्त, अनुकूलन बाण्ड, अनुकूलन हेतु ऋण स्वैप एवं पारस्थितिकी तंत्र सेवा भुगतान का सुझाव दयिा गया है ।
- **सुधार:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार से गैर-ऋण नधियिों तक पहुँच में सुधार हो सकता है ।
- **परिवर्तनकारी प्रभाव:** क्षमता नरिमाण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजनाओं के तहत वभिनिन क्षेत्रों में वकिस प्राथमकितताओं में अनुकूलन को बढ़ावा देने के साथ परिवर्तनकारी प्रभाव हेतु क्षमता नरिमाण पर बल देना चाहयि ।

UNDERSTANDING THE UNFCCC NEGOTIATIONS A TIMELINE OF THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE



THE 'FRAMEWORK' FOR INTERNATIONAL CLIMATE ACTION, UNFCCC

UNFCCC SIGNED - 1992

The original UN climate treaty. Established the basic framework and principles for international climate change action. Developed countries committed to take the lead with developing countries agreeing to take action with financial and technological support as they developed. No legally emission targets agreed for any countries.

NEGOTIATING PROCESS AND COMMITMENT PERIODS OF THE KYOTO PROTOCOL

KYOTO PROTOCOL SIGNED - 1997

Requires industrialized countries to make a collective binding emission cut of 5% below 1990 levels by 2012. Introduced innovative new instruments, including the Clean Development Mechanism. US never ratified. First commitment period (2008-12) covered 50% of 1990 global emissions. Second commitment period coverage down to ~15% as Canada, Japan, Russia and New Zealand join US in opting-out and developing country emissions grow.

NEGOTIATING PROCESSES UNDER THE UNFCCC FOR A NEW GLOBAL CLIMATE DEAL TO COMPLEMENT OR REPLACE THE KYOTO PROTOCOL

COPENHAGEN ACCORD - 2009

Lima must build on the momentum generated by key climate events of 2014 e.g. Ban Ki-moon's Climate Summit in September and China-US announcement in November about limiting emissions. In particular, it must reach agreement on: the elements of a draft negotiating text for new global climate deal; the form and structure of countries' targets and measures for the new deal; and how to enhance ambition in the pre-2020 period. Without these, reaching an ambitious deal at COP21 in Paris next December will be put at risk.

NEW GLOBAL TREATY TO BE AGREED - 2015

Process to agree new treaty covering all countries was established at COP17 Durban in 2011. Governments have to disclose their targets and measures in March, and then conclude negotiations in Paris in December 2015, with treaty in force from 2020. The goal is a global climate agreement covering all countries that will reduce greenhouse gas emissions to a level that will keep the expected rise in Earth's mean surface temperature below 2°C in order to avoid the worst climate change impacts.

नषिकर्ष

अडैप्टेशन गैप रपिर्ट, 2024 में विकासशील देशों को सहायता देने के क्रम में अनुकूलन वित्तपोषण तथा अभिनव समाधानों पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। इस रपिर्ट में वैश्विक जलवायु एजेंडे के तहत जलवायु अनुकूलन के महत्त्व को रेखांकित करने के साथ अनुकूलन वित्त अंतराल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो UNFCCC COP29 वार्ता का नरिणायक बटु बना हुआ है।

दृष्टिमेन्स प्रश्न

प्रश्न: UNEP की अडैप्टेशन गैप रपिर्ट, 2024 में पहचाने गए वैश्विक जलवायु अनुकूलन प्रयासों से संबंधित वित्तीय एवं रणनीतिक अंतराल पर चर्चा करने के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न: वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा ।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमति करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2C या कोशशि करें कि 1.5 C से भी अधिक न होने पाए ।
3. वकिसति देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतहासकि जमिमेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लयि वकिसशील देशों की सहायता के लयि 2020 से प्रतवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतबिद्धता जताई ।

नीचे दए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: "मोमेंटम फॉर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल कसिके द्वारा प्रवर्तति की गई है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) UNEP सचविालय
- (c) UNFCCC सचविालय
- (d) वशिव मौसमवज्जान संगठन

उत्तर: (c)